(c) Approximately 1543 cases in major units of BHEL.

(d) Since employment on compassionate grounds is need-based, it is difficult to fix a time frame for disposing of all such requests.

एच०एम०टी कारखाना, अजमेर का कार्यकरण

3559. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एच०एम०टी०) के कितने कारखाने हैं और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अजमेर स्थित एच०एम०टी० कारखाने ने गत तीन वर्षों में उत्पादन-लक्ष्य हासिल किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अजमेर स्थित एच०एम०टी० कारखाने की उत्पादन क्षमता का विस्तार एवं आधुनिकीकरण करने के लिए कोई योजना बनायी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर कितना खर्च किए जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) एच०एम०टी० की 22 यूनिटों के राज्य-वार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:—

आंध्र प्रदेश	4	असम	1
हरियाणा	2	जे० एंड के०	1
केरल	2	कर्नाटक	8
महाराष्ट्र	1	पंजाब	8
राजस्थान	1	यू०पी०	1

(ख) और (ग) तीन वर्षों के दौरान, एच०एम०टी० की अजमेर यूनिट का उत्पादन लक्ष्य तथा वास्तविक उपलब्धि निम्न प्रकार है:—

(रुपये लाख में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	प्राप्ति प्रतिशत
1995-96	2285	2857	125
1996-97	2800	3775	135
1997-98	3800	3736	98

कमी का कारण, ग्राहक द्वारा माल उठाने में हुआ विलम्ब रहा है।

(घ) और (ङ) एच०एम०टी०, कंपनी के लिए एक पुनरुद्धार योजना पर काम कर रही है। विस्तार तथा आधुनिकीकरण को पुनरुद्धार योजना के एक भाग रूप में समझा जा सकता है।

Steps to remove bottlenecks in Industrial policies

3560. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that liberalisation is not delivering the desired results in the industrial sector in the country;

(b) whether Government have identified the bottlenecks in the industrial policies of the Central and State Governments;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the action Gvoernment propose to take to remove these bottlenecks so that more and more industries are set up in the country?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT) (a) to (d) The process of economic liberalisation started in the year 1991-92, resulted in the increased industrial production during 1993-94, 1994-95 and 1995-96, when the growth rate improved by 6.0%, 8.4% and 12.7% respectively. However, inspite of strong fundamentals of the economy there was a slow down in the growth of the industrial production during 1996-97 and 1997-98, when the industrial sector grew by 5.6% and 6.6% respectively. This slow down in the industrial production was due to a combination of factors which include slump in the capital market, dampening investment activity, infrastructural constraints and sluggish export growth which was due to decline in the growth of world trade.

The review of the Industrial policy is an on-going process. The recent steps taken for liberalising the Industrial Policy

and streamlining the procedures include further delicensing of industries; 35% increase in plan outlay on the infrastructure; permitting Foreign Direct Investment (FDI) up to Rs. 1500 crore for power projects through the automatic approval route and time bound clearance for FDI proposals in general.

उद्योगों में महिला उद्यमी

3561. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय विभिन्न उद्योगों में महिला उद्यमियों का कुल प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या सरकार ने औद्योगिक एकक स्थापित करने हेतु महिला उद्यमियों के लिए कोई प्रोत्साहन योजना तैयार की है;

(ग) ऐसे कौन-कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनमें महिला उद्यमियों का प्रतिशत सर्वाधिक है; और

(घ) प्रति वर्ष प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों में से महिला आवेदकों की संख्या का अनुपात / संख्या का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) द्वितीय अखिल भारतीय पंजीकृत लघु औद्योगिक एकक संगणना (उपलब्ध अद्यतन स्थिति) के अनुसार 31.03.1988 को लघु क्षेत्र में महिला उद्यमियों की प्रतिःशतता 7.69% थी। बड़े और मझौले क्षेत्र की महिला उद्यमियों से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, हां। नये औद्योगिक एककों को स्थापित करने के लिए महिला उद्यमियों को प्रदान किये जा रहे अनेक प्रकार के प्रोत्साहन निम्नलिखित हैं:—

—भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिड्बी) द्वारा महिला उद्यमियों के लिए पुनः पुनर्वित-पोषण योजना

–सिड्बी द्वारा महिला उद्यम निधि योजना के अंतर्गत सुलभ ऋण (सॉफ्ट लोन) के माध्यम से इक्विटी जैसी सहायता।

—सिड्बी ने महिलाओं के लिए कुछ विकासात्मक कार्यक्रम बनाये हैं जैसे कि महिला विकास निधि, लघु (माइक्रो) ऋण योजना, महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम, ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम और विपणन विकास निधियां।

-लघु उद्योग सेवा संस्थान (एस॰आई॰एस॰आई॰) राज्य उद्योग निदेशालय और बैंक महिलाओं के लिए उद्यमियता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन अनन्य रूप से कर रहे हैं।

—प्रधानमंत्री रोज़गार योजना (पी॰एम॰आर॰वाई॰) के अंतर्गत महिलाओं को औद्योगिक एककों व्यवसाय और सेवा उद्यमों की स्थापना करने के लिए तरजीह दी जाती है।

—सरकार ने महिलाओं में उद्यमियता का अनन्य रूप से विकास और संवर्धन करने के लिए "व्यापार संबद्ध उद्यमियता सहायता और विकास (ट्रेड)" नामक शीर्षक कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

(ग) प्रधान मंत्री रोज़गार योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों का अधिकतम संकेन्द्रण आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाया गया था।

(घ) प्रधानमंत्री रोज़गार योजना जिसके अंतर्गत उद्योग, सेवा और व्यवसाय क्षेत्र है, के अंतर्गत वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 की अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है:—

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	महिलाओं से प्राप्त आवेदनों की संख्या / अनुपात
1995-96	9,60,162	90,333 (9.4%)
1996-97	8,90,746	90,847 (10.2%)
1997-98	7,69,972	90,036 (12.1%)

Integrated Infrastructural Developme.

3562. DR. JAGANNATH MISHRA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the scheme of Integrated Infrastructural Development (IID) (including Technical back up Services) for Small Scale Industries in rural and backward areas is not becoming successful;

(b) if so, the reasons therefor and the remedial steps being taken to make it a success;